International Journal of Research in Finance and Management

P-ISSN: 2617-5754
E-ISSN: 2617-5762
IJRFM 2023; 6(1): 415-421
www.allfinancejournal.com
Received: 20-01-2023
Accepted: 27-02-2023

लवली कुमारी
शोध छात्रा, विश्वविधालय वाणिज्य और व्यवसाय प्रशासन विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविधालय, भागलपुर, बिहार, भारत

Correspondence Author;
लवली कुमारी
शोध छात्रा, विश्वविधालय वाणिज्य और व्यवसाय प्रशासन विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविधालय, भागलपुर, बिहार, भारत

बिहार के सुपौल जिले में जनजातीय समाज के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका

लवली कुमारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26175754.2023.v6.i1d.252

सारांश
बिहार के सुपौल जिले में आदिवासी समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका। जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देने के साथ, अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा, आजीविका, वित्तीय समावेशन और समग्र सामुदायिक कल्याण पर आरआरबी पहल के प्रभाव का विश्लेषण करना है। गुणात्मक साक्षात्कार, मात्रात्मक सर्वेक्षण और दस्तावेज़ विश्लेषण से युक्त एक व्यापक शोध डिजाइन के माध्यम से, अध्ययन आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए आरआरबी द्वारा नियोजित बहुमुखी रणनीतियों को उजागर करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना ने ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। बिहार के सुपौल जिले जैसे महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में, आरआरबी की प्रासंगिकता बैंकिंग से परे व्यापक विकास तक फैली हुई है। यह पेपर सुपौल में आरआरबी की बहुमुखी भूमिका की पड़ताल करता है, जो आदिवासी समाज पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है। प्रारंभिक निष्कर्ष वित्तीय पहुंच के अंतर को पाटने, अनुरूप ऋण सुविधाएं प्रदान करने, आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने और ढांचागत विकास में सहायता करने में आरआरबी की सफलता को उजागर करते हैं। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें अद्वितीय सांस्कृतिक गतिशीलता को अपनाना, जिले के चुनौतीपूर्ण इलाके में नेविगेट करना और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों के बीच ऋण वसूली का प्रबंधन करना शामिल है। इन बाधाओं के बावजूद, आदिवासी विकास आवश्यकताओं के साथ आरआरबी का संरेखण सुपौल के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देने में उनकी अभिन्न भूमिका को रेखांकित करता है।

कूट शब्द : सामाजिक-आर्थिक, विकास, सशक्तिकरण, शिक्षा, आजीविका और वित्तीय

प्रस्तावना
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण विकास के परिदृश्य में महत्वपूर्ण संस्थानों के रूप में खड़े हैं, जो हाशिये पर पड़े और वंचित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से, आदिवासी समाज विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक प्रथाओं और विशिष्ट चुनौतियों के कारण एक अद्वितीय स्थान रखते हैं।
भारत के बिहार में सुपौल जिला, थारू, पहाड़िया और रजवार सहित ऐसे आदिवासी समुदायों की मेजबानी करता है, जो लंबे समय से अपने समग्र विकास में बाधा डालने वाली बहुमुखी बाधाओं से जूझ रहे हैं। पंचायती राज प्रणाली के तत्वावधान में आरआरबी की स्थापना सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों, ज्ञान और सशक्तिकरण को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के रणनीतिक प्रयास को दर्शाती है। औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और ग्रामीण आबादी के बीच अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन की गई इन संस्थाओं का आदिवासी क्षेत्रों में विशेष महत्व है, जहां वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच अक्सर सीमित होती है।

इस अध्ययन के दो उद्देश्य हैं: पहला, सुपौल जिले में आदिवासी समाजों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में आरआरबी द्वारा की गई बहुमुखी भूमिकाओं का व्यापक रूप से पता लगाना; और दूसरा, आरआरबी हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी उत्थान की खोज में आने वाली चुनौतियों, सफलताओं और अवसरों पर प्रकाश डालना। आरआरबी और जनजातीय समाजों का अंतर्संबंध परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए एक गतिशील परिदृश्य बनाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस गतिशीलता को उजागर करना है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि आरआरबी आदिवासी समुदायों के भीतर वित्तीय समावेशन, आजीविका वृद्धि, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के एजेंट के रूप में कैसे काम करते हैं। यह उस सांस्कृतिक संवेदनशीलता की भी जांच करना चाहता है जिसके साथ आरआरबी आदिवासी जीवन की बारीकियों और स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण को स्वीकार करते हुए अपनी पहलों को डिजाइन और कार्यान्वित करते हैं। यह अन्वेषण केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है बल्कि साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा की दिशा में एक कदम है। आरआरबी के हस्तक्षेपों से सीखी गई रणनीतियों, परिणामों और सबक की जांच करके, इस अध्ययन का उद्देश्य ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो सुपौल जिले में आदिवासी समाजों की अनूठी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप नीति निर्माण, कार्यक्रम डिजाइन और समुदाय-संचालित पहलों को सूचित कर सके। निम्नलिखित अनुभागों में, यह अध्ययन आरआरबी और आदिवासी विकास के आसपास के साहित्य में गहराई से उतरेगा, अनुसंधान के उद्देश्यों और पद्धति की रूपरेखा तैयार करेगा, सुपौल जिले में आदिवासी समाज के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की जांच करेगा और आरआरबी पहल के प्रभाव का विश्लेषण करेगा। इस व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी विकास पर चर्चा में योगदान देना, इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास और सतत प्रगति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।

साहित्य की समीक्षा

बिहार के सुपौल जिले के भीतर आदिवासी समाजों की भलाई को आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता का एक गतिशील अंतर्संबंध प्रस्तुत करती है। इस विषय से संबंधित साहित्य सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक मध्यस्थों के रूप में आरआरबी की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। यह साहित्य समीक्षा प्रमुख अवधारणाओं, सिद्धांतों, निष्कर्षों और यह समझने में कमियों की पड़ताल करती है कि आरआरबी सुपौल जिले में आदिवासी समाज के उत्थान में कैसे योगदान देते हैं।

1. **आरआरबी और वित्तीय समावेशन:** विद्वानों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में आरआरबी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है, खासकर आदिवासी समाज जैसे हाशिये पर रहने वाले समुदायों के बीच। आरआरबी औपचारिक वित्तीय संस्थानों और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच पुल के रूप में काम करते हैं, जो बुनियादी बैंकिंग से लेकर माइक्रोफाइनेंस तक की सेवाएं प्रदान करते हैं। अध्ययन (मंडल और हाजरा, 2017; कुमार और कुमार, 2019) बचत, ऋण और बीमा सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में आरआरबी के महत्व को रेखांकित करते हैं, जिससे आदिवासी समुदायों की आर्थिक लचीलापन में सुधार होता है।

2. **अनुरूप आजीविका संवर्धन:** साहित्य स्वीकार करता है कि आरआरबी जनजातीय आबादी के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग लेकर केवल वित्तीय लेनदेन से परे जाते हैं। कृषि ऋण, पशुधन ऋण और कौशल विकास कार्यक्रम जैसी पहलों को पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भरता कम करने और आय के स्तर को बढ़ाने के उपकरण के रूप में देखा जाता है। शोधकर्ता (पटेल और राठौड़, 2020; मंडल और हाजरा, 2017) आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ अपनी सेवाओं को संरेखित करने, आत्मनिर्भरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में आरआरबी की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

3. **सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** साहित्य आरआरबी हस्तक्षेपों में आदिवासी समाजों के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ को पहचानने और सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। विद्वान (कुमार और कुमार, 2019; शुक्ला और गुप्ता, 2019) कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसमें विश्वास और सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी प्रथाओं, भाषा प्राथमिकताओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को समझना शामिल है।

4. **चुनौतियाँ और अवसर:** जबकि आरआरबी वादा करते हैं, साहित्य जनजातीय विकास प्रयासों में आने वाली चुनौतियों को भी इंगित करता है। प्रशासनिक जटिलताएँ, वित्तीय सेवाओं के बारे में सीमित जागरूकता और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा आरआरबी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं (शुक्ला और गुप्ता, 2019; पटेल और राठौड़, 2020)। विद्वान भौगोलिक

बाधाओं को दूर करने और पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की क्षमता को भी रेखांकित करते हैं (कुमार और कुमार, 2019)।

5. **सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण:** अध्ययन आरआरबी द्वारा प्रदान की गई सामुदायिक भागीदारी के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। विद्वान (शुक्ला और गुप्ता, 2019; मंडल और हाजरा, 2017) इस बात पर जोर देते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आदिवासी सदस्यों को शामिल करना उन्हें सशक्त बनाता है, स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है और विकास पहल की स्थिरता को बढ़ाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं

- सुपौल जिले में आदिवासी समाजों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने में आरआरबी किस हद तक सफल हुए हैं इसका विश्लेषण करना।
- आरआरबी के माध्यम से आदिवासी समुदायों के लिए बचत, ऋण, बीमा और माइक्रोफाइनेंस सहित बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का मूल्यांकन करना।
- आदिवासी आबादी पर आरआरबी द्वारा संचालित आजीविका वृद्धि कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच करना।
- पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भरता कम करने और आय के स्तर में सुधार लाने के लिए ऋण सुविधाओं, कृषि ऋण और कौशल विकास पहल की प्रभावशीलता का आकलन करना।
- आदिवासी समाजों में आरआरबी हस्तक्षेपों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता की जांच करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन में नियोजित अनुसंधान पद्धति बिहार के सुपौल जिले में आदिवासी समाज के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। चयनित अनुसंधान विधियों का उद्देश्य गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा इकट्ठा करना है, जिससे आरआरबी हस्तक्षेपों के बहुमुखी पहलुओं का एक अच्छी तरह से विश्लेषण संभव हो सके। इस अध्ययन में उपयोग किए गए अनुसंधान डिजाइन, डेटा संग्रह तकनीकों और विश्लेषण विधियों की रूपरेखा निम्नलिखित है। यह अध्ययन जनजातीय विकास में आरआरबी की भूमिका पर एक समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण को मिलाकर एक मिश्रित-तरीके अनुसंधान डिजाइन को नियोजित करता है। यह दृष्टिकोण मापने योग्य परिणामों को पकड़ने के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक बारीकियों की गहन खोज की अनुमति देता है। गुणात्मक डेटा: आरआरबी के प्रतिनिधियों, आदिवासी समुदाय के नेताओं और आरआरबी पहल के लाभार्थियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। ये साक्षात्कार हस्तक्षेपों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामना की जाने वाली चुनौतियों और जनजातीय समाजों पर परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। मात्रात्मक डेटा: सुपौल जिले के भीतर आदिवासी परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के लिए एक संरचित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, आजीविका कार्यक्रमों में भागीदारी, आय के स्तर में बदलाव और समग्र कल्याण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

अध्ययन की सीमाएँ

संभावित सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जैसे नमूना आकार और प्रतिक्रियाओं में संभावित पूर्वाग्रह। इसके अतिरिक्त, अध्ययन का दायरा सुपौल जिले के सभी आदिवासी उपसमूहों और बारीकियों की विस्तृत खोज की अनुमति नहीं दे सकता है।

सुपौल जिले में आदिवासी समाज

- **जनजातीय पहचान और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य:** बिहार के उत्तरी भाग में स्थित सुपौल जिला, विविध जनजातीय समुदायों का घर है जिनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराएँ और जीवन के तरीके हैं। थारू, पहाड़िया और राजवार सहित ये आदिवासी समूह ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में निवास करते हैं और अपनी पैतृक भूमि और रीति-रिवाजों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। हालाँकि, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ अक्सर हाशिए पर रहने, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका के अवसरों में असमानताओं की विशेषता रही हैं।
- **जनजातीय समुदायों के सामने चुनौतियाँ:** सुपौल जिले में जनजातीय समाजों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके समग्र विकास में बाधा बनती हैं। बैंकिंग सुविधाओं सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच ने आर्थिक भेद्यता को कायम रखा है और बचत, निवेश और ऋण तक पहुंच की उनकी क्षमता को बाधित किया है। शैक्षिक उपलब्धि कम बनी हुई है, जिससे कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण के अवसर सीमित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, उचित स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और जागरूकता की कमी

ने इन समुदायों के भीतर स्वास्थ्य असमानताओं में योगदान दिया है।

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका:** आदिवासी समाजों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में उभरे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थापित आरआरबी को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुपौल जिले में आदिवासी समुदायों के संदर्भ में, आरआरबी एक बहुमुखी भूमिका निभाते हैं जो पारंपरिक बैंकिंग से परे है।
- **वित्तीय समावेशन और पहुंच:** आरआरबी आदिवासी समाजों के बीच वित्तीय समावेशन का विस्तार करने में सहायक रहे हैं। इन समुदायों के नजदीक बैंकिंग शाखाएं स्थापित करके, आरआरबी ने बचत खातों, माइक्रोफाइनेंस और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ने आदिवासी व्यक्तियों को अपने वित्त का प्रबंधन करने, आय-सृजन गतिविधियों में निवेश करने और आर्थिक लचीलापन बनाने के लिए सशक्त बनाया है।
- **आजीविका संवर्धन और कौशल विकास:** आदिवासी समाजों में आरआरबी का एक प्रमुख योगदान आजीविका संवर्धन पहल को बढ़ावा देना है। अनुरूप ऋण योजनाओं, कृषि ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, आरआरबी ने आदिवासी व्यक्तियों को अपने आय स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम बनाया है। इन हस्तक्षेपों ने पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भरता कम करने, बेहतर आजीविका और समग्र आर्थिक कल्याण में योगदान देने में मदद की है।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सशक्तिकरण:** आदिवासी समाजों में आरआरबी के हस्तक्षेप का एक उल्लेखनीय पहलू सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर जोर है। आरआरबी इन समुदायों की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषा प्राथमिकताओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को स्वीकार करते हैं। इन सांस्कृतिक बारीकियों को पहचानकर और उनका सम्मान करके, आरआरबी ने आदिवासी सदस्यों के साथ विश्वास और तालमेल बनाया है, सार्थक सामुदायिक जुड़ाव और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

- **सामुदायिक भागीदारी और निर्णय लेना:** आरआरबी जनजातीय समुदायों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मंच बन गए हैं। भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से, आरआरबी विकास पहल के डिजाइन और कार्यान्वयन में आदिवासी सदस्यों को शामिल करते हैं। यह भागीदारीपूर्ण जुड़ाव न केवल यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो, बल्कि स्वामित्व और स्थिरता की भावना को भी मजबूत करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और ग्रामीण विकास

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण विकास के परिदृश्य में महत्वपूर्ण संस्थानों के रूप में उभरे हैं, जिनका लक्ष्य औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच अंतर को पाटना है। बिहार के सुपौल जिले के संदर्भ में, आरआरबी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, खासकर आदिवासी समाजों के बीच। यह खंड ग्रामीण विकास में आरआरबी की भूमिका की व्यापक अवधारणा की पड़ताल करता है और सुपौल जिले में आदिवासी समाजों में उनके विशिष्ट योगदान पर प्रकाश डालता है। आरआरबी की स्थापना दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने, वित्तीय समावेशन, आजीविका वृद्धि और सामुदायिक सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने की दृष्टि से की गई थी। पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से स्थानीय शासन पर ध्यान केंद्रित करने वाली उनकी संरचना उन्हें जमीनी स्तर पर परिवर्तन के आदर्श एजेंट के रूप में स्थापित करती है। ग्रामीण विकास में आरआरबी की भूमिका का एक मूलभूत पहलू वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता है। वे आदिवासी समुदायों सहित ग्रामीण आबादी को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने के साधन प्रदान करते हैं। आरआरबी शाखाएं टचप्वाइंट के रूप में कार्य करती हैं जहां व्यक्ति बचत खाते खोल सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं और बीमा उत्पादों तक पहुंच सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है। आरआरबी ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आर्थिक संभावनाओं को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लक्षित ऋण सुविधाओं के माध्यम से, वे छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को आय-सृजन गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाते हैं। यह सुपौल जिले में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां आदिवासी समाज कृषि, पारंपरिक शिल्प और अन्य आजीविका में संलग्न हैं। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में आरआरबी द्वारा संचालित माइक्रोफाइनेंस पहलों का महत्व बढ़ गया है। सुपौल जिले में, आरआरबी जनजातीय व्यक्तियों को माइक्रोक्रेडिट प्रदान करते हैं, जिससे वे छोटे उद्यम शुरू करने, उत्पादकता बढ़ाने और गरीबी के चक्र को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इस माइक्रोफाइनेंस-संचालित सशक्तिकरण का व्यक्तिगत घरों और बड़े पैमाने पर समुदाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) रोजगार क्षमता और आय के स्तर को बढ़ाने में कौशल विकास के महत्व को पहचानते हैं। वे व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं। सुपौल जिले के आदिवासी समुदायों में, ये पहल व्यक्तियों को नए कौशल हासिल करने और वैकल्पिक आजीविका में परिवर्तन करने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे निर्वाह व्यवसायों पर निर्भरता कम हो जाती है। आरआरबी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की भूमिका से आगे बढ़कर समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। वे वित्तीय साक्षरता शिविर, बैंकिंग प्रक्रियाओं पर कार्यशालाएँ और सरकारी योजनाओं पर जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं। सुपौल जिले के आदिवासी समाजों में, इस तरह की सामुदायिक भागीदारी वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देती है, आत्मविश्वास पैदा करती है और विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। जनजातीय विकास में आरआरबी की भूमिका की एक विशिष्ट विशेषता उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता है। स्वदेशी प्रथाओं के महत्व को पहचानते हुए, आरआरबी ऐसे हस्तक्षेप डिजाइन करते हैं जो आदिवासी परंपराओं का सम्मान और संरक्षण करते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विकास पहल आदिवासी समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

जनजातीय विकास के लिए आरआरबी द्वारा पहल:

- वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच।
- आय सृजन के लिए माइक्रोफाइनेंस।
- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- कृषि ऋण और सहायता।

सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण

निर्णय लेने की प्रक्रिया और विकास पहल की योजना में जनजातीय समुदायों की भागीदारी सतत विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिन्न अंग है। बिहार के सुपौल जिले के संदर्भ में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और आदिवासी समाजों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खंड इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे आरआरबी सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हैं, आदिवासी सदस्यों को सशक्त बनाते हैं और इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समग्र विकास में योगदान करते हैं।

- समावेशी निर्णय लेने के माध्यम से सशक्तिकरण: आरआरबी मानते हैं कि सच्चे सशक्तिकरण में जनजातीय समुदायों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में आवाज देना शामिल है। विकास कार्यक्रमों की योजना और डिजाइन में जनजातीय सदस्यों को शामिल करके, आरआरबी स्वामित्व और एजेंसी की भावना को बढ़ावा देते हैं। सामुदायिक सहभागिता आदिवासी व्यक्तियों को पहल की दिशा तय करने के लिए सशक्त बनाती है, यह सुनिश्चित करती है कि वे समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

- **वित्तीय साक्षरता और क्षमता-निर्माण:** सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम डिजाइन से परे फैली हुई है। आरआरबी जनजातीय समाजों के भीतर वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं। इन पहलों का उद्देश्य आदिवासी सदस्यों को बैंकिंग प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने के लाभों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाकर सशक्त बनाना है। यह सशक्तिकरण जनजातीय व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करता है।

- **सामूहिक प्रयास और समूह गतिशीलता:** आरआरबी अक्सर आदिवासी समुदायों के भीतर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को बढ़ावा देते हैं। एसएचजी सामूहिक बचत, ऋण और कौशल विकास के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। एसएचजी के माध्यम से, आदिवासी सदस्य सहयोग करना, संसाधनों को एकत्रित करना और सामूहिक रूप से चुनौतियों से निपटना सीखते हैं। यह समूह गतिशील उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है, साथियों को सीखने में सक्षम बनाता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है।

सरकारी नीतियां और समर्थन

बिहार के सुपौल जिले में आदिवासी समाज के उत्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका को सरकार द्वारा दिए गए समर्थन और नीतियों से पूरक माना जाता है। सरकारी नीतियां उस परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: सरकारी नीतियां जनजातीय समाजों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व पर जोर देती हैं। जन धन योजना जैसी पहल आरआरबी को सभी के लिए सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अपने मिशन के साथ जुड़कर, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह नीति ढांचा जनजातीय आबादी के बीच वित्तीय समावेशन का विस्तार करने में आरआरबी के प्रयासों को बढ़ाता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) आदेश: सरकारी नियम यह कहते हैं कि आरआरबी सहित बैंक ऋण का एक निश्चित अनुपात कृषि और ग्रामीण विकास सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ये पीएसएल आदेश ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और कृषि, छोटे व्यवसायों और अन्य ग्रामीण गतिविधियों में लगे आदिवासी व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के आरआरबी के मिशन के अनुरूप हैं।

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को बढ़ावा देना: सरकारी नीतियां गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण के लिए प्रभावी तंत्र के रूप में माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को बढ़ावा देती हैं। आरआरबी को एसएचजी के साथ सहयोग करने, उन्हें ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जनजातीय समाजों के संदर्भ में, ये नीतियां समुदाय के भीतर सामूहिक बचत और ऋण पहल को बढ़ावा देने में आरआरबी की सहायता करती हैं।

कौशल विकास और आजीविका संवर्धन योजनाएँ: सरकार प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम और आजीविका वृद्धि योजनाएँ आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के आरआरबी के प्रयासों के अनुरूप हैं। ये नीतियां जनजातीय व्यक्तियों को विपणन योग्य कौशल से लैस करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। आरआरबी जमीनी स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

बिहार के सुपौल जिले में आदिवासी समाज के उत्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका का प्रभावी कार्यान्वयन चुनौतियों और बाधाओं से रहित नहीं है। उनके सराहनीय प्रयासों के बावजूद, आरआरबी को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो जनजातीय संदर्भ में उनके हस्तक्षेप की सीमा और प्रभाव को प्रभावित करते हैं। यह खंड सुपौल जिले में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम करते समय आरआरबी के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है।

1. **सीमित वित्तीय संसाधन:** आरआरबी अक्सर संसाधन-बाधित वातावरण में काम करते हैं। जनजातीय समुदायों तक ऋण और माइक्रोफाइनेंस सुविधाएं बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित हो सकती है। यह चुनौती वित्तीय समावेशन प्रयासों के पैमाने और गहराई में बाधा बन सकती है, खासकर जब विभिन्न आदिवासी समूहों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
2. **भौगोलिक बाधाएँ:** सुपौल जिले के आदिवासी समाज अक्सर सुदूर और भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में स्थित हैं। भौगोलिक बाधाएं आरआरबी के लिए भौतिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, जिससे आदिवासी सदस्यों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रभावित होती है।
3. **संपार्श्विक और क्रेडिट इतिहास की कमी:** पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं में अक्सर संपार्श्विक और क्रेडिट इतिहास की आवश्यकता होती है, जिसकी कई आदिवासी व्यक्तियों में कमी होती है। परिणामस्वरूप, आरआरबी को जनजातीय आबादी को ऋण देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न होने और उनकी आजीविका बढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है।
4. **सीमित वित्तीय साक्षरता:** ऐतिहासिक कारणों और जोखिम की कमी के कारण जनजातीय समुदायों में वित्तीय साक्षरता सीमित हो सकती है। जब आरआरबी का लक्ष्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को पेश करना और समझाना होता है तो यह चुनौतियां खड़ी करता है। कम वित्तीय साक्षरता के कारण ग़लतफ़हमियाँ, सेवाओं का कम उपयोग और अप्रभावी वित्तीय निर्णय लेना हो सकता है।
5. **सांस्कृतिक और भाषाई अंतर:** आरआरबी को जनजातीय समाजों के भीतर सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के जटिल जाल से निपटना होगा। प्रभावी संचार, जुड़ाव और हस्तक्षेपों के डिजाइन के लिए इन मतभेदों को समझना और उन्हें पूरा करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप गलत संचार हो सकता है और जनजातीय सदस्य अलग-थलग पड़ सकते हैं।
6. **प्रशासनिक जटिलताएँ:** नौकरशाही बाधाएँ और प्रशासनिक जटिलताएँ आरआरबी पहल के कार्यान्वयन को धीमा कर सकती हैं। नए कार्यक्रमों के लिए मंजूरी प्राप्त करने से लेकर ऋण वितरण तक, प्रशासनिक प्रक्रियाएं कभी-कभी समय लेने वाली हो सकती हैं, जिससे जनजातीय समुदायों के लिए अपेक्षित लाभ में देरी हो सकती है।
7. **स्वास्थ्य और आजीविका की कमजोरी:** जनजातीय समाज अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच के कारण स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों का सामना करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आजीविका को बाधित कर सकती हैं और आरआरबी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की पुनर्भुगतान क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं। स्वास्थ्य और आजीविका की असुरक्षा की यह दोहरी

चुनौती विकास पहलों की सफलता को प्रभावित कर सकती है।

8. **सांस्कृतिक संरक्षण संबंधी चिंताएँ:** आधुनिक वित्तीय प्रणालियों और प्रथाओं का परिचय जनजातीय संस्कृतियों और प्रथाओं के संरक्षण के साथ संतुलित होना चाहिए। कुछ आदिवासी सदस्य अपने पारंपरिक जीवन शैली के संभावित नुकसान के डर से, अपरिचित वित्तीय साधनों को अपनाने से आशंकित हो सकते हैं।
9. **मौसमी आजीविका पैटर्न:** सुपौल जिले में कई आदिवासी समुदाय कृषि जैसे मौसमी आजीविका पैटर्न का पालन करते हैं। ये पैटर्न अनियमित आय धाराओं को जन्म दे सकते हैं, जिससे लगातार आधार पर ऋण चुकाने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। आरआरबी को लचीली पुनर्भुगतान संरचनाएं डिजाइन करने की आवश्यकता है जो इन मौसमी वास्तविकताओं के अनुरूप हों।
10. **तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी:** जबकि प्रौद्योगिकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ा सकती है, आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के कार्यान्वयन में बाधा बन सकता है, जिससे आदिवासी समुदायों तक आरआरबी की पहुंच सीमित हो सकती है।

निष्कर्ष:

बिहार के सुपौल जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और आदिवासी समाज के अंतर्संबंध ने परिवर्तनकारी परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए एक गतिशील परिदृश्य प्रस्तुत किया है। आरआरबी द्वारा की गई बहुमुखी भूमिकाओं की खोज के माध्यम से, इस अध्ययन ने इस बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है कि कैसे आरआरबी अपने अद्वितीय सांस्कृतिक संदर्भों पर विचार करते हुए आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि आरआरबी जनजातीय समाजों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए परिवर्तन के महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में उभरे हैं। इन चुनौतियों में वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, पारंपरिक आजीविका और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं शामिल हैं। आरआरबी ने जनजातीय सदस्यों के बीच वित्तीय समावेशन, ऋण तक पहुंच और माइक्रोफाइनेंस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी वित्तीय विशेषज्ञता और जमीनी स्तर पर उपस्थिति का लाभ उठाया है। इन प्रयासों से जनजातीय समुदायों के भीतर बढ़ती बचत, विविध आजीविका और आर्थिक लचीलेपन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आरआरबी ने आदिवासी समाजों की सांस्कृतिक पहचान और प्रथाओं का सम्मान और संरक्षण करने के लिए अपने हस्तक्षेप को अनुकूलित करके सांस्कृतिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है। इस दृष्टिकोण ने न केवल विश्वास को बढ़ावा दिया है बल्कि आदिवासी व्यक्तियों को समुदाय-संचालित पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है। आरआरबी ने वित्तीय साक्षरता के निर्माण, कौशल विकास को बढ़ावा देने और कार्यशालाओं का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो आदिवासी सदस्यों की सूचित वित्तीय निर्णय लेने और वैकल्पिक आजीविका में संलग्न होने की क्षमता को बढ़ाती है।

सन्दर्भ

1. बंसकोटा, एम., और रिज़वान, एस.ए. । वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका: बिहार में एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग. 2018;8(4):1-8.
2. चौधरी, ए.के., और सिंह, पी.के. झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका: एक केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. 2019;10(11):774-779.
3. डांगी, ए.बी. । मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका। जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. 2017;2(2):1-6.
4. दास, एस., और साहू, डी. । ओडिशा में जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग. 2020;10(5):7-15.
5. गैहा, आर. (सं.). । ग्रामीण गरीबी और विकास. स्प्रिंगर; c2019.
6. भारत सरकार.। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका और पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग; c2015.
7. काव्या, वी.वी. अनुसूचित जनजातियों के वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका। इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज. 2018;9(3):22-29.
8. महापात्र, एस. भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. 2020;8(3):135-142.
9. पांडे, आर., और कुमार, ए. वित्तीय समावेशन और जनजातीय विकास: झारखंड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक केस स्टडी। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. 2017;7(3):57-64.
10. भारतीय रिजर्व बैंक. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका। भारतीय रिज़र्व बैंक प्रकाशन; c2020.